(b) Does not arise.

(c) and (d) DTC's losses have been increasing on account of following factors :—

(1) Uneconomic fare structure of DTC.

(2) Rising costs of labour and material inputs.

(3) Concessions given to students and weaker sections of the society through concessional passes.

(4) Heavy interest burden on the loans advanced etc.

The total accumulated losses as on 31-3-91 is. Rs. 64551·10 lakhs (provisional).

राजमार्गों पर यात्रियों को सुविधायें दिया जाना

2576. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यात्रियों को राजमार्गों पर कम से कम प्रत्येक 100 किलो मीटर के अन्तराल पर सुविधायें प्रदान करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से पहले ही दी जा चुकी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय उत्तर प्रदेश में कोई मार्गस्थ सुविधायें चालू नहीं हुई हैं ।

(ग) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों को मार्गस्थ सुविधायें सुलभ कराने के प्रयोजनार्थ चुना गया है ।

सरकारी क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत :

(i) एन एच-2 के कानपुर-वाराणसी खंड पर 115 कि० मी० खागा के समीप ।

(ii) एन एच 29 पर गाजीपुर ।

(iii) एन एच 29 पर दोहरी घाट ।

निजी क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत : (जिसके लिए संबंधित पार्टियों को आशय पत्र जारी कर दिए गए हैं)

(i) गढ़ मुक्तेश्वर से लखनऊ खंड में दिल्ली से 131 कि० मी० एन० एच–24

(ii) सीतापुर की तरफ बरेली से 35 कि० मी०–एन एच-2

(iii) वाराणसी की तरफ इलाहाबाद से 32 कि० मी० एन० एच–2

(iiv) बरेली-रामपुर खंड पर 192.60 कि० मी०, एन एच–24

(v) पूर्वी बनारस 86 मि० मी० एन एच–56

(vi) दिल्ली-गढ रोड से 100 कि० मी० एन एच–24

सड़कों के अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व को निर्धारित करना

2577. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़कों के अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व को निर्धारित करने के क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत किए गए निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है और यह कार्य किन-किन क्षेत्रों में किया गया है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश के उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जहां इस योजना के अधीन 1991–92 के दौरान निर्माण कार्य किया जा रहा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) मोटे तौर पर मानदण्ड इस प्रकार है, अर्थात्:—

(i) संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय सड़कें/पुल,

(ii) नए क्षेत्रों के लिए जहां निकट भविष्य में रेलवे सुविधायें सुलभ नहीं कराई जा सकती, अपेक्षित सड़कें/पुल, और

(iii) सडकें/पुल जो पर्वतीय क्षेत्रों और दोहन के लिए समृद्ध खनिज संसाधनों वाले स्थानों के तीव्र आर्थिक विकास के लिए काफी योगदान कर सकते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश में अंतर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केंद्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए कोई कार्य अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) स्थिति इस प्रकार है अर्थात्

(i) लखनऊ-बागरमऊ-बिल्हौर रोड पर उन्नाव जिला में नानामऊ घाट पर गंगा पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।

(ii) उ० प्र० बिहार बार्डर पर माझीघाट के समीप घाघरा पर पुल का निर्माण।

(iii) मेरठ जिला में मेरठ-सोनीपत रोड पर बागपत के समीप यमुना पर पुल का निर्माण।

(iv) बरेली जिला में पानीपत-खातिमा से बरूर तक सड़क का निर्माण। निर्माण।

Co-operative Housing Scheme at Paradip Port

2578. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRIMATI MIRA DAS :

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether there is any proposal from Paradip Port Trust to his Ministry for approval of Co-operative Housing Scheme run by port employees and dock workers to overcome the inadequate quarter facilities at Paradip ; and

(b) if so, what are the details thereof and the ction taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) and (b) A proposal for allotment of 14 acres of land in favour of Paradip Port Trust Employees Cop-operative Credit Society Ltd. for a period of thirty years for construction of houses for the Paradip Port Trust employees on payment of land premium of Rs. 50,000/- per acre and ground rent of 2% of the premium was received from Paradip Port in October, 1990. It was examined but not agreed to.

2579. [*Transferred to the 19th December, 1991*]

2580. [*Transferred to the 19th December, 1991*]

2581. [*Transferred to the 19th December 1991*]

Negotiations with foreign shipyards

2582. SHRI MENTAY PADMANABHAM : Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item appearing in the Financial Express of November 28, 1991 captioned "Shipping Policy being finalised";

(b) if so, what are the proposals under Government's consideration for selling of equity in various Government owned shipyards in the present context;

(c) whether any negotiations have been held with any foreign shipyards for participation in the equity of existing shipyards ; and

(d) the number of ships giving total tonnage which were purchased from foreign yards in 1990-91 by both private and public sector shipping companies?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER) : (a) Yes, Sir.

(b) There is no proposal under consideration for selling of euqity of various Government owned Shipyards.

(b) No, Sir.